

प्रेषक,

संख्या- 45/XXVII(1)/2009

एल०एम० मन्त,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून :: दिनांक: 20 जनवरी, 2009

विषय:- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की चतुर्थ त्रैमासिक किस्त हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नगर निगम देहरादून को चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की चतुर्थ त्रैमासिक किस्त हेतु ₹0 24289000.00 (रुपया दो करोड़ बयालीस लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

(1) 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07 में विभिन्न शासनादेशों द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹0 29370000.00 (₹0 दो करोड़ तिरानबे लाख सत्तर हजार मात्र) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रशासनिक विभाग से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन की चतुर्थ किस्त से समायोजित कर लिया गया है।

(2) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं०-1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(3) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि के बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।



(4) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(5) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-191-नगर निगम-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करें से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।

संख्या- 45 (1)/XXVII(1)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
- 3- सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 5- निदेशक, नगरीय स्थानीय निकाय, देहरादून।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 8- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

20/11/2009
(एल0एम0 पन्त)
सचिव।